रजिस्टर्ड नं0 एल0-33/एस0 एन0/13-14/96.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 9 अगस्त, 1996/18 श्रावण, 1918

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 जुलाई, 1996

संख्या पी0 0 एच0-एच0 ए0 (1) 12/87-10406-606.—हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 94 का 4) की धारा 11 (2), 83 (1) और 94 (1) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज-संस्थाओं को संलग्न अनुबन्ध के अनुसार शक्तियों, कार्यों तथा दायित्वों को सौंपने के सहर्ष आदेश देते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-

वित्तायुक्त एवं सचिव ।

अनुबन्ध

कृषि विभाग

जिला परिषद्	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत
1	2	3
(क) कृषि उत्पादन योजना को तैयार करना :		
1. जिलों के कृषि उप-निदेशक तथा जिला कृषि अधिकारी के साथ परामर्श करने के उपरान्त विकास खण्डों के लिए कृषि उत्पादन योजना को अनुमोदित करना तथा इसका जिला स्तर पर समेकित करना ।	1. विकास खण्ड स्तर पर कार्यरत कृषि विकास अधिकारी के साथ परामर्श के उपरान्त कृषि उत्पादन योजना को तैयार करना तथा समेकित कर जिला परिषद् को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना ।	1. विस्तार कर्मचारी के परामर्श के बाद पंचायत के लिये कृषि उत्पादन योजना को तैयार करके पंचायत समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना ।
(ख) कृषि उत्पादन सामग्री की आपूर्ति का प्रबन्ध करना :		
2. कृषि उत्पादन सामग्री की मांग को समय पर विकास खण्डों/ग्राम पंचायतों में आपूर्ति हेतु जिला स्तरीय अधिकारी के परामर्श से समेकित कर उचित प्रबन्ध करना ।	2. पंचायतों से इकट्ठी की गई मांग को समेकित कर इसे जिला परिषद् को प्रस्तुत करना ।	2. पंचायत के लिये कृषि उत्पादन सामग्री की मांग को निर्धारित करना और पंचायत समिति को व्यवस्था करने हेतु समय पर पर प्रस्तुत करना ।
(ग) कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण:		
3. कृषि विस्तार कार्यकलापों का अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण ।	3. कृषि विस्तार कार्यकलापों का अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण ।	3. सम्बन्धित पंचायतों के विभागीय विस्तार कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन्नत तकनीकी का कृषकों में प्रदर्शन करना एवं प्रशिक्षण देना ।
(घ) भू एवं जल संरक्षण :		
4. अनुमोदित योजनाओं/स्कीमों को कार्यान्वित करने हेतु स्त्रोतों को पंचायत समितियों को आबंटित करना तथा कार्यकुशलता एवं स्त्रोतों के उपयोगिता का अनुश्रवण करना।	4. जिला परिषद् द्वारा स्त्रोतों के आबंटन के अन्तर्गत पंचायतों से प्राप्त योजनाओं को अनुमोदित करना तथा अनुमोदित योजनाओं के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना ।	4. भू एवं जल संरक्षण स्कीमों का कृषि विभाग से सम्बन्धित कर्मचारियों के परामर्श से तैयार करना तथा पंचायत समिति के अनुमोदनोपरान्त इन्हें कार्यान्वित करना तथा सिंचाई

		स्कीमों के अन्तर्गत जो कृषि भूमि है उसको पंचायत स्तर पर विभाग के प्रसार कर्मचारी के परामर्श से कृषि उत्पादन कार्यक्रम का प्रस्तुतीकरण करना तथा इसे कार्यान्वित करना ।
(ङ) बायोगैस विकास :		
5. पंचायत समितियों को वित्तीय स्त्रोतों का उपलब्ध करना तथा इस कार्यक्रम की प्रगति का समय-समय पर अनुश्रवण करना ।	5. पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों का अनुमोदन तथा इनका विभाग के कर्मचारियों के तकनीकी परामर्श द्वारा कार्यान्वित करना तथा प्रगति का समय-2 पर अनुश्रवण करना ।	5. लाभार्थियों को पहचान करना और विभाग के कर्मचारियों के तकनीकी परामर्श के अधीन प्रस्तावों को पंचायत समिति को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना ।
(च) पौध संरक्षण :		
6. पौध संरक्षण औषधियों की मांग को समय पर पंचायत समितियों से एकत्रित कर विभाग को इनकी प्राप्ति हेतु प्रेषित करना तथा विभाग से प्राप्त इन औषधियों को वितरण हेतु पंचायत समितियों को उपलब्ध करवाना । औषधियों की आपूर्ति तथा पौधों की बीमारियों पर सघन रूप से निगरानी करना तथा इनके प्रकोपों की अवस्था में जिला स्तरीय तथा राज्य स्तरीय अधिकारियों को इनके उन्मूलन हेतु समय-समय पर सूचित करना ।	6. पौध संरक्षण औषधि की मांग की आपूर्ति हेतु जिला परिषद् के माध्यम से उचित प्रबन्ध करवाना । तथा विक्रय केन्द्र द्वारा उनका वितरण करवाना । बीमारियों के प्रकोपों पर सघन रूप से निगरानी करना तथा प्रकोप की अवस्था में समय-समय पर जिला परिषद् तथा राज्य मुख्यालय को इनके उन्मूलन हेतु सूचित करना ।	6. पंचायत स्तर पर कृषि विभाग के प्रसार कर्मचारियों के माध्यम से पौध संरक्षण और कीटाणु प्रबन्धन अभियान चलाना । पौध संरक्षण औषधियों की मांग को एकत्रित कर इनकी आपूर्ति/वितरण हेतु पंचायत समिति को प्रेषित करना । पौधों की बीमारियों पर निगरानी रखना तथा इनके प्रकोप की अवस्था में पंचायत समिति, जिला परिषद तथा राज्य मुख्यालय को इनके उन्मूलन हेतु समय-समय पर सूचित करना ।
पशुपालन विभाग		
1. जिलों में पशुपालन कार्यक्रमों की योजना तैयार करना ।	1. जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु औषधालय भवनों का निर्माण एवं रख-रखाव करना ।	1. दुग्ध एकत्रण केन्द्रों/समितियों की देख-भाल करना ।
2. पशुओं की छूत की बीमारियों एवं उनके बचाव/रोकथाम हेतु निगरानी रखना ।	2. पशु मेलों, प्रदर्शनियों, बछड़ों की रैलियों, पशुधन प्रदर्शनियों का आयोजन करना ।	2. पशुधन कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों की पहचान एवं उनकी सिफारिश करना ।

1	2	3
3. राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त जिला स्तर पर चारा एवं चारा विकास योजना को कार्यान्वित करना ।	3. पशुपालन नीति (योजना) के अन्तर्गत ब्लाक स्तर पर तालमेल रखना ।	3. गांवों में समय-समय पर पशु संस्थानों/कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का निरीक्षण, देख-रेख तथा इनको सुचारू रूप से चलाने हेतु सिफारिश करना ।
4. जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु औषधालयों का संचालन एवं उनके भवनों के निर्माण तथा मुरम्मत कार्य का निरीक्षण ।	4. पशु स्वास्थ्य एवं नसबन्दी शिविरों के आयोजन हेतु सिफारिशें करना ।	4. बुध, ऊन/कुक्कट सहकारी समितियों का उत्थान/गठन करना ।
		5. पशुओं/कुक्कटों को महामारी फैलने बारे निकट के पशु संस्थानों तथा ब्लाक स्तर पर विभागीय कार्यकर्ताओं को सूचित करना ।
	आयुर्वेद विभाग	
1. जिला औषधालयों सहित भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग के अस्पतालों के संचालन, अनुरक्षण और निर्माण का पर्यवेक्षण ।	1. भारतीय चिकित्सा पद्धति के औषधालय एवं स्टाफ भवनों का निर्माण एवं रख-रखाव ।	1. आयुर्वेद विभाग में कार्यरत फार्मासिस्ट एवं ए0 एन0 एम0/महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रामीणों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं पंचायत के प्रतिनिधियों में से औषधालय कल्याण सलाहकार समितियों का गठन करना जो प्रत्येक औषधालय द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं तथा सुधार की देख-रेख करेगी । समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि आयुर्वेद विभाग का स्टाफ नियुक्ति के स्थान पर रहता है । समिति का अध्यक्ष ग्राम पंचायत का प्रधान होगा ।
2. यह सुनिश्चित करना कि आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सक और स्टाफ अस्पतालों में नियुक्ति के स्थान पर रहते हैं ।	2. भारतीय चिकित्सा पद्धति औषधालयों के अधीन मुफ्त स्वास्थ्य कैम्प आयोजित करना।	2. भारतीय चिकित्सा पद्धति औषधालय एवं भवनों को सही हालत में रखना एवं अनुसरण करना ।
	3. भारतीय चिकित्सा पद्धति औषधालयों के भवनों का निर्माण एवं अनुरक्षण ।	3. स्कूल स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम एवं परिवार कल्याण स्वास्थ्य कैम्पों का आयोजित करना ।
	4. यह सुनिश्चित करना कि विभाग के कर्मचारी भारतीय चिकित्सा पद्धति औषधालयों में, नियुक्ति के स्थान पर रहते हैं ।	

1. जिला में उच्च पाठशालाओं के अध्यापकों/उपकरणों इत्यादि का आवश्यकता अनुसार निर्धारण करना तथा तदानुसार योजना बनाना ।	1. मिडल स्कूलों की कारगुजारी का निरीक्षण करना ।	1. प्राईमरी स्तर के स्कूल जाने वाले सभी बच्चों की प्रविष्टि को सुनिश्चित करना ।
2. शैक्षणिक सेवाओं की गुणवत्ता एवं स्तर का निरीक्षण एवं संचालन ।	2. मिडल स्कूलों में सामग्री एवं उपकरणों की आपूर्ति एवं वितरण ।	2. प्राथमिक स्कूलों के भवनों एवं खेल के मैदान इत्यादि का रख-रखाव ।
3. पूर्ण उपस्थिति वारे प्रचार एवं स्कूल छोड़ने की प्रवृति को कम करना ।	3. स्कूल छोड़ने की स्थिति का जायजा एवं इसे कम करने के लिये उचित कार्यवाही करना ।	3. प्राईमरी स्कूल के अध्यापकों, गैर-शिक्षक कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति पर सतर्कता एवं सम्बन्धित अधिकारियों को उसकी सूचना देना ।
4. निर्धारित लक्षित समूह के विद्यार्थीगण के लिए छात्रावासों की आवश्यकता का निर्धारण करना तथा योजना बनाना ।	4. मिडल स्कूलों की वर्दी, किताबों एवं अन्य सामग्री का लक्षित समूह के विद्यार्थियों में वितरण ।	4. प्राथमिक पाठशालाओं के लक्षित समूह के छात्रों में पाठ्य सामग्री के वितरण में सहायता करना ।
5. उच्च पाठशालाओं के लक्षित समूह के विद्यार्थीगण में वर्दी, किताबों इत्यादि के वितरण का पर्यवेक्षण ।	5. मिडल स्कूलों के छात्रावासों के रख-रखाव में सहायता करना ।	5. दोपहर के भोजन की योजना का पर्यवेक्षण ।
6. दस जमा दो पाठशालाओं के अध्यापकों, विद्यार्थियों एवं गैर-शिक्षक कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति के सम्बन्ध में सतर्कता और सम्बन्धित प्राधिकारी को रिपोर्ट करना ।	6. उच्च पाठशालाओं के भवनों तथा अन्य सम्बन्धित बुनियादी ढांचों का रख-रखाव ।	
	7. मिडल/हाई स्कूलों के अध्यापकों, गैर-शिक्षक कर्मचारियों और विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति के सम्बन्ध में सतर्कता और सम्बन्धित प्राधिकारी को रिपोर्ट करना ।	

मत्स्य विभाग

1. सरकार के अनुमोदित मानक के अनुसार एफ0 एफ0 डी0 ए0 स्कीम के अधीन अधिकतम 5 हैक्टेयर जल	1. सरकार के अनुमोदित/एफ0 एफ0डी0 ए0 मानक के अनुसार एफ0 एफ0 डी0 ए0 स्कीम	1. सरकार के अनुमोदित/एफ0एफ0डी0ए0 मानक के अनुसार एफ0 एफ0

1	2	3
ढांचे के लिए सभी वैधानिक औपचारिकताओं के पूर्ण करने और एफ0 एफ0 डी0 ए0 के पदाधिकारियों द्वारा वस्तुतः सत्यापन के अध्याधीन रहते हुए तालाबों के निर्माण हेतु रुपये 40,000 से रुपये 1.00 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत करना। धन राशि की अदायगी एफ0 एफ0 डी0 ए0 द्वारा होगी।	के अधीन अधिकतम 3 हैक्टर जल ढांचे के लिए सभी वैधानिक औपचारिकताओं के पूर्ण करने हेतु और एफ0 एफ0 डी0 एफ0 पदधारियों द्वारा वस्तुगत सत्यापन के अध्याधीन रहते हुए तालाबों के निर्माण और मुरम्मत के लिए रुपये 24,000 और रुपये 80,000 की आर्थिक सहायता स्वीकृत करना। धन की अदायगी सम्बन्धित एफ0 एफ0 डी0 ए0 द्वारा होगी।	डी0 ए0 स्कीम के अधीन अधिकतम एक हैक्टर जल ढांचे के लिए सभी वैधानिक औपचारिकताओं के पूर्ण करने और एफ0 एफ0 डी0 ए0 के पदधारयों द्वारा वस्तुगत सत्यापन के अध्याधीन रहते हुए तालाबों के निर्माण और मुरम्मत के लिए 8,000 रुपये और 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत करना। धन की आदयगी सम्बन्धित एफ0 एफ0 डी0 ए0 द्वारा होगी।
2. मत्स्य अधिनियम के अक्रीन सम्यक रूप से अन्य सुरक्षित जल ढांचों और मत्स्य अभ्यारणों से अवैध रूप से मछलियां पकड़ने वालों से शास्ति वसूल करने और अधिरोपित करने की शक्ति।	2. मत्स्य विभाग की सहायता से मत्स्य पालन में प्रशिक्षण के लिए मत्स्य पालकों की पहचान करना और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।	2. सामुदायिक तालाबों के निर्माण के लिए स्थलों की पहचान करना।
3. मत्स्य अधिनियम के अधीन सम्यक रूप से अधिसूचित करना, सम्बन्धित जल-खण्डों को विकसित करना और उनका अनुरक्षण, प्रशिक्षण करना।	3. मत्स्य पालकों को मत्स्य बीजों का वितरण करना और बीजों की मांग एकत्रित करना।	3. वर्तमान सामुदायिक तालाबों की मुरम्मत करना और नये सामुदायिक तालाबों का निर्माण करना।
4. मत्स्य पालन को विकसित करना और प्रोत्साहित करना।	4. मछली पालन को विकसित और प्रोत्साहित करना।	4. लाभार्थियों के सामुदायिक तालाबों को पट्टे पर देना और पट्टा राशि वसूल करने का अधिकार।
5. मत्स्य विभाग की सहायता से मत्स्य बीज उपलब्ध करवाना और उनकी आपूर्ति करवाना।	5. विपणन के लिये सहकारी समितियों द्वारा पंचायत समिति क्षेत्र में मत्स्य उत्पाद के निपटान के लिए विपणन की सहायता उपलब्ध करवाना।	5. सामुदायिक तालाबों का नियन्त्रण और रख-रखाव करना।
		6. ग्राम पंचायत की अधकारिता के भीतर नदियों और नालों के जलीय प्राणी समूह का परीक्षण करना।

		7. ग्राम पंचायत की अधिकारिता के भीतर आने वाली नदियों व नालों में अवैध रूप से मछली पकड़ने वाले मछुआरों को जुर्माना करने/ अधिरोपित करने और जुर्माना वसूलने की शक्ति ।
	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	
1. उचित मूल्य की दुकानें/गोदाम खोलने हेतु सफारिश करना ।	1. आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व परिवहन का पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करना तथा पंचायत समिति क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनरीक्षण करना ।	1. उपभोक्ताओं के हित में पंचायत के कार्यक्षेत्र में आने वाली उचित मूल्य की दुकानों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण करना ।
2. अपने कार्यक्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का पुनरीक्षण व स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकताओं के आधार पर वस्तुओं की मांग का आक्कलन करना ।	2. उचित मूल्य की दुकानों के अन्तर्गत लाए गए उपभोक्ताओं का अनुमान लगाना, विशेषत: कमज़ोर वर्गों के उप भोक्ताओं का ।	2. शिकायत प्रतितोष एजैन्सी के रूप में कार्यों का निपटान व उचित मूल्य की दुकानों पर आवश्यकता पड़ने पर निर्देश जारी करना ।
	3. जाली राशन कार्डों को समाप्त करने लिए योजना बनाना व समुचित पग उठाना ।	3. राशन कार्ड बनाना व जारी करना ।
	4. अपने कार्यक्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानों को खोलने की सिफारिश करना/योजनाओं को बनाना/पुनरीक्षण करना ।	4. जाली राशन कार्ड समाप्त करना ।
	5. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाओं का अन्य कल्याण योजनाओं के साथ समन्वय ।	5. उचित मूल्य की दुकानों के स्थान निश्चित करना ।
	6. जिला परिषद् को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे सूचना तथा विवरणी भेजना ।	6. उचित मूल्य की दुकानों को चलाने के लए आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय स्त्रोतों/धन का प्रबन्ध करना ।

1	2	3
	7. उपभोक्ता संरक्षण/कल्याण की सूचना का प्रसार/प्रचारण ।	7. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जवाहर रोजगार योजना (JRY), एकीकृत ग्रामीण विकास (IRDP), समेकित बाल विकास रेरियोजना (ICDS), ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का विकास भोजन (DWCRA व अपराह्न) का भेजने (Mid-day Meals Scheme) इत्यादि के साथ जोड़ने हेतु पंचायत समिति को कार्ययोजना तैयार करने के लिए सहायता प्रदान करना ।
	वन विभाग	
(क) अन्य वनीकरण योजना :		
1. सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के परामर्श से पंचायत समितियों द्वारा प्रस्तावित अल्पार्थक योजनाओं को अन्तिम रूप देना एवं अनुमोदन ।	1. ग्राम पंचायत द्वारा सम्बन्धित वन परिक्षेत्राधिकारी के समन्वय से चिन्हित भूमि हेतु योजनाओं को तैयार करना जिसमें नर्सरी की स्थापना भी शामिल है ।	1. स्थानीय वन रक्षक/उप-वन परिक्षेत्राधिकारी के परामर्श से शामलात सामुदायिक तथा गैर-वन भूमि को वनीकरण हेतु चिन्हित करना । इसमें स्थान एवं प्रजातियों का पौधारोपण हेतु चयन तथा उस क्षेत्र का विवण जिसमें रख-रखाव की आवश्यकता है, भी समिम्लित है ।
2. वार्षिक कार्य योजना का वन विभाग को प्रस्तुतिकरण तथा वन विभाग द्वारा निधि का आबंटन, जिला परिषदों को पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों में आगामी आबंटन हेतु प्रेषण । अनुमोदित अल्पार्थक योजनाओं के अनुसार लक्ष्यों का निर्धारण ।	2. ग्राम पंचायतों द्वारा भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार अल्पार्थक योजनाओं के निष्पादन को सुनिश्चित करना ।	2. ग्राम पंचायत द्वारा अल्पार्थक योजनाओं का निष्पादन ।
3. वन विभाग को लेखा तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण ।	3. जिला परिषद् को समेकित लेखा तथा प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण ।	3. पंचायत समितियों को मासिक लेखा तथा भौतिक व वित्तीय प्रतिवेदनों का प्रस्तुतिकरण ।

4. गतिविधियों का अनुश्रवण/मूल्यांकन ।	4. ग्राम पंचायतों के प्रबन्ध/सुरक्षा दायित्वों को सुनिश्चित करना ।	4. निर्मित परिसम्पत्ति के प्रबन्ध का दायित्व जिसमें रख-रखाव तथा परिसम्पति की सुरक्षा भी सम्मिलित है ।
5. लाभांश पर किसी भी विवाद का निपटारा करना एवं इसका मूल्यांकन करना ।	5. प्रेरणास्त्रोत का कार्य एवं लाभांश सुनिश्चित करना ।	5. निर्मित सम्पति से प्राप्त लाभांश का सरकार की निति के अनुसार वितरण ।
6. कार्यान्वित कार्य योजना का मूल्यांकन ।	6. कार्य योजना को अनुमोदन करना ।	6. उपरोक्त जुटाए गए संसाधनों से प्राप्त राशि का विकास कार्यों में निवेश करने के लिए सुझाव देना और उसका कार्यान्वियन करना ।
(ग) वनों की आग :		
7. तालमेल/निगरानी एवं मूल्यांकन ।	7. वनों की आग से बचाने के लिए ग्राम पंचायत को विभिन्न निर्देश एवं कार्यविधि प्रेषित करना ।	7. वनों को आग से बचाने के लिए स्थानीय लोगों का सहयोग सुनिश्चित करना तथा वनों में लगी आग को बुझाने के लए अग्नि शमन समिति का गठन करके वन विभाग को सहायता देना ।
8. वन विभाग को बार-बार जुर्म करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने बारे, जैसे टी0 डी0 के हक-हकूक समाप्त करना इत्यादि की सिफारिश करना ।	8. बड़े जुर्म और बार-बार जुर्म करने वालों को सजा देने बारे सिफारिश करना ।	8. उन लोगों के बारे में, जो आग बुझाने में सहायता न करें, रिपोर्ट करना ।
9. जंगल में आग के मामलों का मूल्यांकन तथा भिन्न व्यक्तियों को अथवा जिस पंचायत ने इस बारे बहुत उत्तम काम किया हो उन्हें पुरस्कृत करने हेतु सिफारिश करना । यह पुरस्कार वन विभाग के माध्यम से दिया जाएगा ।	9. समेकित रिपोर्ट भेजना ।	9. समयबद्ध रिपोर्ट भेजना ।

1	2	3
(घ) लघु वन उपज :		
10. लोगों में लघु वन उपज के कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना ।	10. जरूरत से ज्यादा निकाली गई सम्पाद बारे मूल्यांकन करना तथा इसे सुचारू रूप से निकालने के लिए वन विभाग को सुझाव देना ।	10. लघु वन उपज की उपलब्धता का मूल्यांकन करना तथा इसके नाजायज इस्तेमाल पर रिपोर्ट करना ।
(ङ) अतिक्रमण :		
11. नाजायज कब्जे को छुड़ाने के लिए वन विभाग के साथ तालमेल करना ।	11. सम्बन्धित वन परिक्षेत्राधिकारी को मासिक समेकित रिपोर्ट उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित करना ।	11. नाजायज कब्जों के बारे में सम्बन्धित डी(एफ0 ओ0 को रिपोर्ट करना ।
(च) नाजायज कटान/शिकार :		
12. नाजायज कटान तथा शिकार के न करने के बारे में लोगों में जागरुकता पैदा करना तथा इन जुर्मों का मूल्यांकन करना ।	12. सम्बन्धित वन परिक्षेत्र अधिकारी को इस सम्बन्ध में आगामी कार्यावाही हेतु समेकित रिपोर्ट भेजना ।	12. वनों में नाजायज कटान व शिकार को रोकना और इसकी रिपोर्ट सम्बन्धित डी0एफ0 ओ0 को देना । वन रक्षक द्वारा अपनी बीट में की गई गश्त पर निगाह रखना ।
	13. अपने क्षेत्र में वर्गीकरण पौधरोपण और नर्सरी कार्यों का पर्यवेक्षण एवं सम्बन्धित वन अधिकारी को सूचित करना ।	13. अपने क्षेत्र में वनीकरण पौधरोपण और नर्सरी कार्यों का पर्यवेक्षण एवं सम्बन्धित वन अधिकारी को सूचित करना ।
	14. वन विभाग के भू-संरक्षण कार्य का पर्यवेक्षण ।	14. वन विभाग के भू-संरक्षण कार्य का पर्यवेक्षण ।
	15. वन्य प्राणियों के अभिरक्षा का पर्यवेक्षण ।	15. वन्य प्राणियों के अभरक्षा का पर्यवेक्षण ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

1. ग्रामीण अस्पतालों और सी0एच0सी0 के कार्यकलापों की देख-रेख करने, उनमें सुधार लाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इनमें कार्यरत सभी कर्मचारी अपनी नियुक्ति के स्थान पर रहते हैं, हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति का गठन करना। मण्डलीय अस्पतालों, जिला अस्पतालों और रैफरल अस्पतालों को समिति के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया है। जिला परिषद् के अध्यक्ष, समिति के सभापति तथा अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षक, खण्ड चिकित्सा अधिकारी और जिला परिषद के सदस्य इसके सदस्य होंगे।

2. समिति टी0बी0, लैपरोसी तथा एडस जैसे संक्रामक रोगों तथा महामारियों का नियन्त्रण करने हेतु नीति निर्धारण करेगी तथा आई0 ई0 सी0 (सूचना, शिक्षा तथा प्रसार) का अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों सहित, बढ़ावा देना।

3. परिवार कल्याण कार्यक्रम, टीकाकरण तथा स्वास्थ्य शिक्षा हेतु शिविरों का आयोजन करने के लिए योजना तैयार करना।

1. स्वास्थ्य उप-केन्द्रों और आवासीय भवनों का निमार्ण।
2. समिति के क्षेत्र में स्थानीय पंचायत की सहायता से विभागीय शौचालयों का निमार्ण।

3. राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु परिवार नियोजन शिविरों का आयोजन और राष्ट्रीय कार्यक्रमों बारे जागरूकता पैदा करने हेतु मेलों व प्रदर्शनियों का आयोजन करना।

4. अपने क्षेत्र में संक्रामक रोगों, महामारियों से निपटाने हेतु विभागीय कर्मचारियों के सहयोग से प्रभावशाली पग उठाना।

5. स्वास्थ्य संस्थानों के कार्यकलापों की देख-रेख व उनमें सुधार लाने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सी0डी0 स्तर तक सभी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सलाहकार समितियों का गठन करना जिनमें खण्ड चिकित्सा अधिकारी पंचायत समिति के सदस्य, गैर-सरकारी संगठनों के सदस्य, पुरुष/महिला सुपरवाईजरज इत्यादि शामिल होंगे। अध्यक्ष पंचायत समिति उक्त समिति की अध्यक्षता करेंगे। समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सी0 डी0 में कार्यरत सभी कर्मचारी अपनी नियुक्ति के स्थान पर निवास करते हैं।

1. प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान के कार्यकलापों की देख-रेख तथा उनमें सुधार लाने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सलाहकार समितियों का गठन करना जिनमें पंचायत सदस्य, औपिनियन लीडर प्रशिक्षित दाईयां, पुरुष/महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि इत्यादि भी शामिल होंगे। पंचायत प्रधान जिनके क्षेत्र में स्वास्थ्य संस्थान पड़ता है, समिति की अध्यक्षता करेंगे। समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि स्वास्थ्य उप-केन्द्रों में नियुक्त सभी कर्मचारी अपनी नियुक्ति के स्थान पर रहते हैं।

2. सफाई, रास्तों तथा नालियों की समुचित सफाई, स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने हेतु कुओं, बावड़ियों को कलोरिन युक्त करना तथा आवारा कुत्तों को मारने और ठिकाने लगाने की व्यवस्था करना।
3. स्कूल स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम का आयोजना करना।
4. डी0डी0टी0 स्प्रे के दौरान स्प्रे करने वाली टीम की सहायता करना।

5. परिवार नियोजन उपायों को अपनाने/टीकाकरण इत्यादि बारे जनता को प्रोत्साहित करना और ऐसे शिविरों का आयोजन करना।

1	2	3
		6. आन्त्रशोथ और किसी अन्य महामारी के फैलनें बारे विभाग को सूचित करना और स्वास्थ्य समितियों की सहायता से रोकथाम उपाय आरम्भ करना ।
		7. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करना ।
		8. ग्रामीण स्तर पर नालियों का रख-रखाव तथा निर्माण और कूड़े-कचरें का निवारण करना ।
	उद्यान विभाग	
1. पंचायत समितियों को सौंपे गये औद्यानिकी से सम्बधित सभी कार्यों/गतिविधियों की समीक्षा/अनुश्रवण व देख-रेख ।	1. ग्राम पंचायतों को सौंपे गए औद्यानिकी सम्बंधी सभी कार्यों/गतिविधियों की समीक्षा/ /अनुश्रवण व देख-रेख ।	1. लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए उद्यान विभाग की विभिन्न उपदान स्कीमों के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन एवं पहचान करना ।
2. उद्यान विभाग के साथ औद्यानिकी विकास के सभी कार्यक्रमों के लिए समन्वय/सम्पर्क बनाए रखना ।	2. औद्यानिकी इनपुट (कीटनाशक, फंफूद नाशकों को छोड़कर) की वितरण प्रणाली को नियोजित करना ।	2. किसान सभाओं व औद्यानिकी उत्पादक सहकारी सभाओं के गठन को बढ़ावा देना ।
3. अभियानों, मेलों, भेंटवार्ताओं, प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों आदि का आयोजन ।	3. बागवान प्रशिक्षण शिवरों, अध्ययन भ्रमणों, संगोष्ठियों आदि का आयोजन करना ।	3. फलों के लिए मण्डी मध्यस्थ योजना/ समर्थन मूल्य स्कीम के अन्तर्गत फल प्रापण केन्द्रों की देख-रेख करना ।
4. औद्यानिकी उत्पादन के लिए पैकिंग सामग्रियों के प्रापण तथा वितरण में समन्वय व अनुश्रवण ।	4. औद्यानिकीय उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नत प्रजातियों, तकनिकों/पैकेज आफ प्रैक्टिसिज आदि पर प्रदर्शनों का आयोजन करना ।	4. ग्रामवार उद्यान गणना का संचालन ।

5. मण्डी मध्यस्थ योजना/समर्थन मूल्य के अन्तर्गत फलों के प्रापण में समन्वयन व अनुश्रवण ।		5. प्रत्येक जलागम के लिए कार्य योजना तैयार करना ।
		6. औद्यानिकी उत्पादों की पैकिंग सामग्रियों का प्रबन्ध, प्रापण व वितरण करना ।

उद्योग विभाग

1. विभाग की जिला कार्यकारी योजना पंचायत समिति से विचार-विमर्श के उपरान्त महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जिला परिषद् को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाएगी तथा उसके पश्चात् निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश को प्रेषित की जाएगी ।	1. महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा तैयार की गई विभाग की जिला कार्यकारी योजना के प्रारूप पर पंचायत समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जाएगा जिसमें अग्रिम बैंक अधिकारी भी भाग लेगा ।	1. —
2. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र प्रत्येक माह विभिन्न बैंकों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए प्रेषित प्रकरणों की सूची भेजेंगे । इसके अतिरिक्त वह पिछले सिफारिश किए गए ऋण प्रकरणों की वर्तमान स्थिति से भी अवगत करवाएंगे । सम्बन्धित बैंक प्रत्येक माह मूल्यांकन हेतु ऋण चूककर्ता की सूची जिला परिषद् को भेजेगा । महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र इसी तरह की सूचना विभागीय ऋणों के सम्बंध में जिला परिषद् को उपलब्ध करवाएगा ।	2. औद्योगिक इकाईयों को ऋण प्रदान करने के सिफारिश की गई पत्र की प्रतिलिपि महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा समिति को पृष्ठांकित की जाएगी ।	2. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत को सिफारिश किए गए ऋण प्रकरणों की प्रतिलिपि भेजेंगे ।
3. जिला परिषद् द्वारा उपलब्ध कुशलता से सम्बन्धित सूचना को एकत्रित किया जाएगा तथा औद्योगिक इकाईयों की आवश्यकता ऐच्छिक व्यक्तियों की सूची तैयार करके तथा उस पर प्राथमिकता अंकित करके उद्योग विभाग को कुशलता विकास कार्यक्रमों के आयोजन हेतु भेजी जाएगी ।	3. उद्योग विभाग द्वारा सम्बन्धित पंचायत समिति को उनके क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों में मानव शक्ति कुशलता की जानकारी दी जाएगी । पंचायत समिति द्वारा उस क्षेत्र में उपलब्ध कुशलता की सूचना दी जाएगी । यदि किसी विशेष प्रकार की दक्षता उपलब्ध न हो तो पंचायत	3. —

1	2	3
	समिति द्वारा जिला परिषद् को ऐसे व्यक्तियों की सूची उपलब्ध करवाई जाएगी जो इस विशेष दक्षता को सीखने के लिए इच्छुक हों।	
4. जिला परिषद् द्वारा औद्योगिक जागरूकता एवं उद्यमी विकास कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आवश्यक सूचना को एकत्रित करना। इसके अतिरिक्त विशेष वर्गों जैसे अनुसूचित जाति जनजाति महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक और अन्य वर्गों के सम्बध में जानकारी प्राप्त करना ताकि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सके। इसके उपरान्त जिला परिषद् द्वारा प्राथमिकता अंकित करके कार्यक्रमों के आयोजन के लिए उद्योग विभाग को सिफारिश की जाएगी।	4. पंचायत समिति द्वारा अपने क्षेत्र में औद्योगिक जागरूकता कार्यक्रम/औद्योगिक विकास कार्यक्रम के आयोजन के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाएगा तथा प्रस्तावित व्यक्तियों के समूहों का भी चयन किया जाएगा जिसकी सूचना जिला परिषद् को भेजी जाएगी।	4. —
5. प्रधान मन्त्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण स्वीकृत व्यक्तियों को महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जिला उपमण्डल तथा खण्ड स्तर पर विकासायुक्त लघु उद्योग भारत सरकार के निदेशों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है। जिला टास्क फोर्स समिति में अध्यक्ष जिला परिषद्/पंचायत समिति द्वारा किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाएगा।	5. प्रधानमन्त्री रोजगार योजना तथा ग्रामीण दस्तकार/ग्रामीण औद्योगिक योजना के अन्तर्गत लाभार्थी दस्तकारों की पहचान व चयन का कार्य खण्ड स्तर पर किया जाता है। अध्यक्ष पंचायत समिति एक सदस्य को मनोनीत करेगा जो इन योजनाओं के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों की पहचान व चयन करेगा। प्रसार अधिकारी उद्योग इस चयन समिति का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया जाएगा। प्रधान मन्त्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण प्रकरणों को तैयार व उनकी समीक्षा महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा की जाएगी।	5. —
	6. (1) पंचायत समिति ग्राम पंचायत की रेशम गतिविधियों से सम्बन्धित सिफारिशों पर विचार करेगी तथा अन्तिम निर्णय बजट प्रावधान को मध्यनजर रखते हुए किया	6. ग्राम पंचायत शहतूत फार्मों/नर्सरियों तथा चौकी केन्द्रों की स्थापना के लिये उपयुक्त भूमि के टुकड़ों को चिन्हित करेगी

	जाएगा ।	तथा पंचायत समिति को इस पर उचित निर्णय लेने की सिफारिश करेगी ।
	(2) इसी अवधि के दौरान पंचायत समिति स्वयं भी अपने क्षेत्र में पड़ने वाली पंचायत में ऐसे केन्द्रों को स्थापित करने के प्रस्ताव आरम्भ कर सकती है ।	
	(3) यह कोकून के विपणन का कार्य करेगी ।	
	(4) सम्बन्धित मण्डलीय रेशम अधिकारी इस योजना के लिये रखी गई निधि बजट को मध्यनजर रखते हुए पंचायत समिति के निर्णयों को कार्यन्वित करेंगे ।	
6. (1) जिला परिषद् पंचायत समिति द्वारा रखे गए प्रस्तावों पर विचार करेगी तथा जो उसे उचित लगे वह निर्णय लेगी ।	7. (1) पंचायत समिति, ग्राम पंचायतों द्वारा अपने क्षेत्रों को दी गई योजनाओं का परीक्षण करेगी तथा इन पर जिला परिषद् की सिफारिश करने से पहले उचित कार्यवाही करेगी ।	7. ग्राम पंचायत औद्योगिक क्षेत्रों/बस्तियों को स्थापित करने के प्रस्ताव को अग्रेषित कर सकती है बशर्ते इस के लिए पंचायत में पर्याप्त भूमि का टुकड़ा उपलब्ध हो ।
(2) जिला परिषद् यदि उचित समझे तो किसी भी पंचायत समिति के लिए स्वयं भी भूमि को चिन्हित कर सकती है ।	(2) सम्बधित पंचायत समिति स्वयं भी अपने क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों/बस्तियों को स्थापित करने हेतु भूमि को चिन्हित कर सकती है तथा निर्णय के लिए ऐसे प्रस्तावों को जिला परिषद् को भेज सकती है ।	—
8. इस समय सम्भावित उद्यमी अपनी परियोजनाओं को अनुमोदन एवं पंजीकरण के उपरान्त औद्योगिक प्लाट एवं शैड प्राप्त करने के लिए महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को प्रार्थना-पत्र देते हैं । जिला स्तर पर प्लाट आबंटन समिति जिसका अध्यक्ष महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र तथा जिला परिषद् का एक सदस्य होगा के द्वारा सभी प्रार्थना-पत्रों पर विचार के उपरान्त प्लाटों एवं शैडों का आबंटन किया जाता है । इस आबंटन	—	—

1	2	3
के समय में उद्यमियों की आवश्यकता प्लाटों एवं शैडों की उपलब्धता तथा सरकार की नीति को ध्यान में रखा जाता है ।		
	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग	
1. एक से अधिक विकास खण्डों को लाभान्वित करने वाली, जलसंदाय सहित, सम्भावित योजनाओं की पहचान ।	1. जल प्रदूषण की रोकथाम और नियन्त्रण ।	1. हड पम्पों का सरसरी रख-रखाव । कर्मचारी विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे ।
2. विभिन्न प्रकार की योजनाओं के कार्यों के निष्पादन के समय विभाग के कर्मचारियों, ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों द्वारा धन के दुरुपयोग तथा भ्रष्ट तरीके अपनाने सम्बन्धी मामलों को सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के उपयुक्त प्राधिकारी के ध्यान में लाना ।	2. एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाली, जल संदाय सहित, सम्भावित योजनाओं की पहचान ।	2. एक लाख या इससे कम धनराशि निर्मित पेयजल या सिंचाई की योजनाओं का सरसरी रख-रखाव ।
	3. विभिन्न प्रकार की योजनाओं के कार्य निष्पादन के समय विभाग के कर्मचारियों, ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों द्वारा धन के दुरुपयोग तथा भ्रष्ट तरीके अपनाने सम्बन्धी मामलों को सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के उपयुक्त प्राधिकारी के ध्यान में लाना ।	3. जल प्रदूषण की रोकथाम और नियन्त्रण ।
		4. ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत सम्भावित योजनाओं की पहचान ।
		5. चालू पेयजल परियोजनाओं की स्थिति से सम्बन्धित सूचनो पंचायत द्वारा विहित प्राधिकारी को दी जाएगी ।

		6. विभिन्न प्रकार की योजनाओं के कार्य निष्पादन के समय विभाग के कर्मचारियों, ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों द्वारा धन के दुरुपयोग तथा भ्रष्ट तरीके अपनान सम्बन्धी मामलों को सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग के उपयुक्त प्राधिकारो के ध्यान में लाना ।

लोक निर्माण विभाग

1. गांव के सम्पर्क मार्ग, खच्चर सड़कें, गांव के रास्तों, कल्वर्टस और इन सड़कों तथा रास्तों पर 10 मी0 स्पैन तक बने चलने वाले पुलों की पहचान ।	1. खच्चर सड़कों की पहचान, निर्माण तथा रख-रखाव तथा गांवों के सम्पर्क मार्गों की पहचान ।	1. गांवों के सम्पर्क मार्गों की पहचान ।
2. पंचायत समिति द्वारा जैसे कि सड़कों तथा कल्वर्टस का निर्माण और इन सड़कों तथा रास्तों पर बने 10 मी0 स्पैन वाले पुलों के कार्यों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करना ।	2. पंचायत समिति से सम्बन्धित भवनों का निर्माण तथा रख-रखाव ।	2. गांवों के रास्ते, कल्वर्टस तथा गलियों की पहचान, निर्माण तथा रख-रखाव ।
3. जिला परिषद् से सम्बन्धित भवनों का निर्माण तथा रख-रखाव ।	3. उन ग्रामीण सड़कों का रख-रखाव जोकि लोक निर्माण विभाग द्वारा पंचायती राज संस्था को स्थानान्तरित की गई हैं ।	3. गांवों के रास्तों पर आने वाले नालों पर 10 मीटर स्पैन तक बने छोटे पुलों का निर्माण तथा रख-रखाव ।
4. पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित भवनों के निर्माण कार्य का निरीक्षण ।	4. गांवों के रास्तों तथा खच्चर सड़कों पर आने वाली नदियों को पार करने के लिए झूलों का निर्माण तथा रख-रखाव ।	4. ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित भवनों का निर्माण तथा रख-रखाव ।
5. विभिन्न प्रकार की योजनाओं के कार्य निष्पादन के समय विभाग के कर्मचारियों, ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों द्वारा धन के घोर दुरुपयोग तथा गलत तरीके अपनाने सम्बन्धी मामलों को विभाग के उपयुक्त प्राधिकारी के ध्यान में लाना ।	5. ग्राम पंचायत द्वारा भवनों के निर्माण का निरीक्षण ।	5. विभिन्न प्रकार की योजनाओं के कार्य निष्पादन के समय विभाग के कर्मचारियों, ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों द्वारा धन के घोर दुरुपयोग तथा गलत तरीके अपनाने सम्बन्धी-मामलों को विभाग के उपयुक्त प्राधि के ध्यान में लाना ।

1	2	3
		2. समय-समय पर विलेज कामन लैण्ड की वास्तविक स्थिति जैसे कि चारा-गाह, बंजर भूमि, पानी के जलाशय, पानी के रास्ते या बांध आदि के कार्यों को अद्योतन करने में समय समय पर मदद करना ।
		3. वैधिक संस्थाओं को भू-सम्बन्धी रिकार्ड (हकूक सम्बन्धी अभिलेख) और इन्तकाल की कार्यवाही को अद्योतन करने में सहायता करना ।
		विलेज कामन लैण्ड आदि का रख-रखाव व सुरक्षा--
		1. सारी सांझी स्थानीय सम्पत्ति को ठीक हालत में रखने की मुख्य जिम्मे-वारी निर्धारित करना । ऐसी सम्पत्ति पर देखभाल करना ताकि उन पर नाजायज कब्जा न हो या ऐसे इस्ते-माल के लिये भूमि का प्रयोग बदल दिये गये हों जो स्थानीय लोगों के प्रयोग में न हो ।
		2. ऐसी जगहों को चिन्हित करना जिन्हें अवैधानिक तरीके से बदल दिया गया हो या गलत इस्तेमाल किया गया हो या उचित अधिकारियों को उसके उचित कार्यवाही के लिये सूचना देना ।
		3. ऐसी अधिकारियों की कार्यवाही करने के लिये साक्षी एकत्रित करने का प्रावधान करने में सहायता देना ।

1. सभी गरीबी उन्मूलन कार्य क्रमों का मूल्यांकन और महिला, अनुसूचित जाति/जन/जाति तथा सामान्य वर्ग के आई0 आर0 डी0 पी0 लाभार्थियों को इन कार्यक्रमों के अधीन लाना ।	1. पंचायत समिति के कार्य क्षेत्र में जिला ग्रामीण अभिकरण द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवाई गई धनराशि का निर्धारित मार्गदर्शिकाओं के अनुरूप उपयोग सुनिश्चित कराना ।	1. आई0 आर0 डी0 बी0 , ट्राईसम तथा डवाकरा कार्यक्रमों की निर्धारित मार्ग-दर्शिकाओं के अनुसार लाभार्थियों की पहचान एवं चयन करना ।
2. विपणन संरचनात्मक ढांचे/विपणन नेट वर्क का विकास करना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं के लिए सम्बन्धात्मक प्रबन्ध करना ।	2. आई0 आर0 डी0 पी0 लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण/जागरूकता शिविरों का आयोजन करना ।	2. आई0 आर0 डी0 पी0/ट्राईसम/ डवाकरा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करना ।
3. विकास कार्यक्रमों को पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के विकास पर संकेन्द्रित करना ।	3. अनुदान एवं ऋण प्रदानकरने हेतू बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करना ।	3. सामुदायिक परिसम्पत्तियों जैसे पंचायत घर, सामुदायिक केन्द्र, महिला/ युवक मण्डल भवनों तथा आई0 आर0 डी0 पी0 खोखों का स्वामित्व एवं रख-रखाव करना ।
4. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अधीन दिये जाने वाले अनुदान एवं ऋण का बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के समन्वय से अनुश्रवण करना ।	4. लाभार्थियों को विकास पत्रिकाओं एवं पुस्तिकाओं के विवरण का अनुश्रवण करना ।	4. ऋण ऋण वसूली के कार्य में वित्तीय संस्थाओं को सहयोग प्रदान करना ।
5. सम्बन्धित क्षेत्रों के लोगों में वाटर शैड (जलागम) मार्ग दर्शिकाओं का व्यापक प्रचार करना ।	5. आई0आर0डी0पी0 इत्यादि कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रदान की गई परिसम्पतियों एवं योजनाओं का अनुश्रवण करना ।	5. आई0 आर0डी0पी0 लाभार्थियों को कच्चा माल उपलब्ध करवाने तथा उत्पादित वस्तुओं के विपणन में सहयोग प्रदान करना ।
6. स्थानीय उपर्युक्त प्रौद्योगिकाओं की पहचान करना ।	6. ऋण वसूली के कार्य में बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं को सहयोग प्रदान करना ।	6. जे0आर0वाई0/आई0जे0आर0वाई0/ सूनिश्चित रोजगार योजना के अधीन किये जाने वाले कार्यों का चयन तथा

1	2	3
		उनके कार्यान्वयन के लिए ग्राम योजनायें तैयार करना ।
	7. ग्रामीण निर्धनों के लिए विभिन्न बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन की देख-रेख करना ।	7. सम्बन्धित विभागों के तकनीकी कर्मचारियों से तकनीकी सहायता प्राप्त करना ।
	8. जवाहर रोजगार योजना/सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत ग्राम पंचायतों को खाद्यानों की पूर्ति में सहयोग करना तथा इसका अनुश्रवण करना ।	8. रोजगार सृजन कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों की पहचान करना ।
	9. इन्दिरा आवास योजना/गांधी कुटीर योजना/ ग्रामीण स्वच्छता /केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों के कार्यन्वयन के पर्यवेक्षण लिए अध्यक्ष पंचायत समिति की में एक कार्यान्वयन समिति गठित होगी । सम्बन्धित उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) खण्ड विकास अधिकारी तथा पंचायत समिति के कुछ सदस्य इस समिति के सदस्य होंगे । यह समिति इन योजनाओं के अधीन लाभथियों के गलत चयन के बारे में लोक शिकायतों का श्रवण एवं निपटारा भी करेगी ।	9. जे0आर0वाई0/ आई0जे0आर0वाई0/ सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत के खाद्यानों का वितरण करना । अध्यक्षता
	10. पंचायत समिति की सामुदायिक परिसम्पतियों के दुरुपयोग को रोकना ।	10. जे0आर0वाई0/आई0जे0आर0वाई0/ सुनिश्चित रोजगार योजना के अधीन सृजत परिसम्पतियों का रख रखाव करना ।
	11. पंचायत समिति की सामुदायिक परिसम्पतियों से प्राप्त उत्पाद की नीलामी कराना ।	11. इन्दिरा आवास योजना/गांधी कुटीर योजना के अधीन लाभार्थियों का चयन करना ।

13. पंचायत समिति स्तर पर साप्ताहिक मण्डियों के लिए/मेला स्थलों का विकास एव रख रखाव करना ।

13. परिसम्पतियों/अनुदान और ऋण दुरुपयोग की सम्बन्धित विभाग को रिपोर्ट करना ।

14. वाटर शैड कार्यक्रम के लिए ग्राम स्तर पर उपभोक्ता समूहों का गठन एवं प्रेरित करना ।

15. जलागम विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेन्सियों तथा अन्य संस्थाओं को सहयोग प्रदान करना ।

16. ग्रामीण मेलों/मण्डियों के लिए स्थलों का विकास एवं उनका रख रखाव करना ।

17. ग्राम पंचायत की सामुदायिक परिसम्पतियों से प्राप्त उत्पाद की नीलामी करना ।

18. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत् स्वास्थ्य तथा समाज एवं महिला कल्याण विभागों क परामर्श से लाभाथियों के चयन में सहयोग प्रदान करना ।

19. राष्ट्रीय उन्नत चुल्हा कार्यक्रम का कार्यान्वयन करना ।

वृद्ध आश्रमों की देख-रेख चलाना तथा असहायक वृद्धों एवं उन्हें आश्रमों में रहने हेतू सहयोग देना ।		
6. मादक द्रव्यों से प्रभावित लोगों में शिक्षा एवं उनमें जागरूकता लाना ।	6. जिला परिषद् के साथ समन्वय स्थापित करना ।	4. पंचायत समिति के साथ समन्वय स्थापित करना ।
7. स्वयं सेवी संगठनों की पहचान करना तथा उन्हें मादक द्रव्यों से प्रभावित लोगों के लिए जागरूकता कैम्प का आयोजन करना तथा नशे की आदत को छोड़ने बारे परामर्श/प्रोत्साहित करना । इन कैम्पों के लिए निधि स्थानान्तरण करना ।		
(ङ) किशोर न्याय प्रशासन :		
8. उपेक्षित एवं अपराधी किशोरों के गृहों का निरीक्षण करना ।	7. जिला परिषद् के साथ समन्वय स्थापित करना ?	5. पंचायत समिति के साथ समन्वय स्थापित करना ।
(च) अस्पृश्यता का उन्मूलन :		
9. नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 को लागू करने के लिए जिला पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करना ।	8. अस्पृश्यता से प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण, अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए सर्व-श्रेष्ट ग्राम पंचायत को पुरस्कृत करना तथा नागरिक सुरक्षा अधिनियम-1955 के अन्त-र्गत जागरूकता लाने हेतू कैम्पों का आयो-जना करना निधि का स्थानान्तरण करना ।	6. अनुसूचित जाति के विरूद्ध भेदभाव पूर्ण प्रथा की पहचान के सम्बन्ध मे :—
10. अस्पृश्यता को समाप्त करने बारे प्रति वर्ष 2 अक्तूबर को (अस्पृश्यता सप्ताह मनाना तथा निधि का स्थानान्तरण ।		(क) सार्वजनिक शमशान घाटों में प्रवेश्यता ।
		(ख) सार्वजनिक पीने के पानी स्रोतों में प्रवेश्यता ।
		(ग) गांव में चाय के ढाबों में अलग बर्तनों का इस्तेमाल ।
		(घ) नाई और धोबी की सेवाओं का नाकारना ।
		(ड़) बारात की शोभा यात्रा निकालना । सम्बन्धित ग्राम पंचायत यह सुनिश्चित करेगी कि

F. Other functions :		
13. —	13. To supervise afforestation, plantation and nursery works within their area and report to the concerned Forest Officer.	13. To supervise afforestation, plantation and nursery works within their area and report to the concerned Forest Officer.
	14. Supervision of soil conservation work of the Forest Department.	14. Supervision of soil conservation work of the Forest Department.
	15. To supervise the protection of wild life.	15. To supervise the protection of wild life.
	HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT	
1. Formation of Health & Family Welfare Advisory Committee to oversee the functioning of C.H.C.'s and Rural Hospitals, improvement thereof and ensure that all the functionaries of these institutions are residing at the places of posting. However, the functioning of Zonal Hospitals, District Hospitals and Referral Hospitals are excluded from the purview of the Committee. The Committee shall be chaired by Chairman of the Zila Parishad and its members shall be Medical Superintendents of these hospitals, B.M.Os. and Zila Parishad members.	1. Construction and maintenance of Health Sub-Centres and staff quarters.	1. Formation of Health & Family Welfare Advisory Committee for sub-centres consisting of Panchayat members, opinion leaders, trained birth attendant Male/ Female Health Workers, NGO representatives etc. to oversee the functioning of each health institutions improvement thereof and ensure that the functionaries of the sub-centre are residing at the places of posting. The Committee shall be chaired by the Pradhan of the Gram Panchayat in whose area institution falls.
2. The Committee shall devise strategy to boost IEC campaign in respect of control measures for all communicable diseases like T. B., Leprosy, AIDS etc. as well as all other National Programmes.	2. Construction and maintenance of Community latrines in the Samiti areas with the help of local panchayat.	2. Sanitation, cleaning of roads, drains, chlorination of wells/ bowlies and destruction of stray dogs and their disposal.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 31*st July*, 1996

No. PCH-HA (1) 12/87-10206-406.—In exercise of powers conferred under section 11(2), 83(1) and 94(1) of Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (4 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to entrust the powers, functions and responsibilities upon the Panchayati Raj Institutions in Himachal Pradesh, as per the enclosed Annexure.

By order,
Sd/-
Financial Commissioner-cum-*Secretary*.

ANNEXURE

AGRICULTURE DEPARTMENT

Zila Parishad 1	Panchayat Samiti 2	Gram Panchayat 3
A. Preparation of Agriculture Production Plan :		
1. To approve agriculture production plan for the Block and consolidate the same at district level in consultation with the Deputy Director, Agriculture & District Agriculture officer of the district.	1. To consolidate and prepare agriculture production plan in consultation with the Assistant Development Officer at Bock level for submission to the zila Parishad for approval.	1. To prepare agriculture production plan for the Panchayat in consultation with the extension staff for submission to the Panchayat Samiti for approval.
B. Arrangements for Agriculture Inputs :		
2. To consolidate demand of inputs and ensure timely arrangements through the district level officer for its supply to the Blocks/ Panchayats.	2. To consolidate demand received from Panchayats and submit to the Zila Parishad.	2. To assess demand of inputs for timely submission to the Panchayat Samiti for arrangements.

1	2	3
C. Agriculture Extension & Training :		
3. Monitoring and supervision of agriculture extension acivities.	3. Monitoring and supervision of agriculture extension activities.	3. To conduct demonstrations on improved technology and training of farmers through extension functionaries of the department for the concerned Panchayats.
D. Soil and Water Conservation :		
4. Resource allocation to Panchayat Samities for execution of approved schemes and monitoring and execution performance vis-a-vis resources utilisation.	4. Approval of schemes received from Panchayats within resource allocations to be made by the Zila Parishad. Monitoring of execution of approved schemes.	4. Identificaton of schemes in consultation with the concerned local staff of the department for submission to the Panchayat Samiti for approval. Approved schemes shall be executed by Panchayat under technical guidance of the staff of the department. The Panchayats shall prepared cropping plans in command areas of irrigation schemes in consultation with the staff of the department for implementation.
E. Biogas Development :		
5. Resource allocation and performance monitoring.	5. Execution of approved cases under technical quidance of the staff of the Department. Perfrmance monitoring.	5. Identification of beneficiaries and submission of proposal to the Panchayat Samiti forapproval under guidance of the technical staff of the Department.
F. Crop Protection :		
6. To consolidate the demand from Panchayat Samitis conveyed to the department and obtain the pesticide from department and further distribute to the Panchayat Samities. Performance moni-	6. To arrange supply of pesticides as per reeuirement through Zila Parishad and distribute through Sale Centres. To ensure closer surveillalance of spread of diseases and timely ties with the Zila Parishad/State	6. To organise crop protection and pest management campaigns under technical guidance of extension functionaries of the department. To assess pesticides requirement and place

toring and closer surveillance over spread of diseases/epidemics and reporting to the district/State Headquarter for immediate control measures.	Headquarter for control measures. Performance monitoring.	demand to the Pahchayat Samiti for arrangement of supply/ distribution of pesticides under technical guidance of the agriculture staff. To ensure closer surveillance o. diseases/epidemics and report to the Samiti/ Zila Parishad/State Headquarters for immediate control measures.

ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

1. Planning of animal husbandry programmes in the district.	1. Construction and maintenance of veterinary dispensary buildings in rural areas in the district.	1. Supervision o milk collection centre/societies.
2. Monitoring oi contagious diseases and popularisation of preventive measures.	2. Conduct of animal fairs, exhibitions, calf-rallies, livestock shows and milk competitions.	2. Identification and recommendation of beneficiaries for animal husbandary programme.
3. Implementation of feed and fodder development schemes at district level after approval of the State Government.	3. Co-ordination in respect of policy planning of animal husbandary programme at block level.	3. Periodical supervision and inspection of veterinary dispensary artificial insemination centtres in the village and recommend the remedial measures.
4. Supervision of functioning and construction and maintenance of veterinary dispensary building in rural areas in the district.	4. Making recommendations for holding of animal health/sterlity camps.	4. To promote the formation oi milk/wool/poultry co-operative societies.
		5. To report outbreak of epidemics diseases amongst livestock/poultry to the nearest veterinary institution and Block level functionary of the department.

AYURVEDA & HOMEOPATHY DEPARTMENT

1. Supervision of the functioning, Construction and maintenance of the hospitals of Indian System of	1. Construction and maintenance of buildings of ISM dispensaries staff quarters.	1. Formation of Dispensary Welfare Advisory Committees with representatives of Panchayats,

1	2	3
Medicine, including the District Hospitals. 2. Ensure that Ayurvedic & Homeopathic doctors and staff reside at the places of postings at Hospitals.	2. Organising free medical camps under I.S.M. dispensaries. 3. Construction and maintenance of buildings attached to I.S.M. dispensaries. 4. Ensure that the Ayurvedic staff reside at the places of postings at I.S.M. dispensaries.	Pharmacist and A.N.M./F.H.W. of Ayurveda Department, Panchayat, Members, N.G. O's etc. to oversee the services provided by each dispensary, improvement thereof and ensure that the Aurvedic staff reside at the places of postings The Committee shall be chaired by the Pradhan of Gram Panchayat. 2. Up-keep and maintenance of I.S.M. dispensaries and quarters. 3. Organising school health check-up programmes and medical and family welfare camps.
	EDUCATION DEPARTMENT	
1. To assess the requirement of High School teachers, equipment etc. in the district and plan for them.	1. To supervies the functioning of middle schools.	1. Ensure full enrolment of school-age children in primary schools.
2. Supervision and monitoring of the quality of educational services.	2. Supply and distribution of material and equipments to the middle schools.	2. Maintenance of primary school buildings, play gronds etc.
3. Campaign for full enrolment and reduction of drop-outs.	3. To assess the drop-out position and initiate appropriate action to reduce it.	3. Vigilance on regular attendance of primary school teachers and non-teaching staff and students reporting to the concerned authorities.
4. Assessment of requirement for hostels of target group students and plan for them.	4. Distribution of middle school uniform, books and other material to the target group students.	4. Assist primary schools in the distribution of study material to the target group students.
5. Supervision of distribution of high school uniforms, books etc. fot target group students.	5. Assist in the maintenance of hostels of middle schools.	5. Supervision of mid-day meal scheme.
6. Vigilance on regular attendance of 10+2 teachers and non-teaching	6. Maintenance of high school buildings and related infrastructure.	

staff and students and reporting to the concerned authorities.		
	7. Vigilance on regular attendance of middle/high school teachers and non-teaching staff and students and reporting to the concerned authorities.	

FISHERIES DEPARTMENT

1. Sanction of subsidy as per approved Government/F. F. D. A. norms for repair and construction of ponds under F.F.D.A. Scheme upto Rs. 40,000/- and Rs. 1,00,000/- respectively for maximum of 5 hectares water body subject to completion of all codal formalities and physical verification by officials of F.F.D.A. the amount will be releasedc by the oncerncd F. F. D. A.	1. Sanction of subsidy as per approved Government / F.F.D.A. norms for repair and construction of ponds under F.F.D.A. scheme upto Rs. 24,000/- and Rs. 80,000/- respectively upto the maximum of 3 hectares water body subject to completion of all codal formalities and physical verification by officials of F. F. D. A. The amount will be released by the concerned F.F.D.A.	1. Sanction of subsidy as per approved Government/F. F. D. A. norms for repair and construction of ponds under F. F. D. A. scheme upto Rs. 8,000/- and Rs. 20,000/- respectively upto the maximum of one hectare water body, subject to completion of all codal formalities and physical verification by by officials of F.F.D.A. The amount will be released by the concerned F. F. D.A.
2. Power to impose and realise penalty from poachers indulging in illegal fishing from Fish Sanctuaries and other protected water bodies duly notified under the Fisheries Act.	2. Identification of fish farmers for training in fish Culture and arranging their training with the assistance of Department of Fisheries.	2. Identification for sites for construction of community ponds. 3. Renovation of existing community ponds and construction of new community bounds. 4. Right to lease community ponds to the beneficiaries and realisation of lease money. 5. Maintenance and control of community ponds.
3. Protection, conservation and development of other protected waters' duly notified under the Fisheries Act.	3. Collection of demand and distribution of seedlings to the fish fammers.	6. Conservation of aquatic fauna of rivers and streams within the jurisdiction of Gram Panchayat.
4. Promotion and development of Fish Culture Programme. 5. Procurement and supply of fish	4. Promotion and development of Fish Culture Programme. 5. Providing marketing assistance in	7. Power to impose and realise fines from the poachers indulging in illegal fishing in the rivers and

1	2	3
seed/fry with the assistance of the Department.	disposal of fish produce within the Panchayat Samiti area by organising co-operative societies for marketing.	streams falling within the jurisdiction of Gram Panchayat.
	FOOD & SUPPLES DEPARTMENT	
1. To recommend the opening of fair price shops/godowns.	1. Supervision and monitoring of movement and availability of essential commodities and review of the public distribution system in the Panchayat Samiti area.	1. To supervise the functioning of Fair Price Shops under the jurisdiction of the Panchayats in the interest of the consumers.
2. To review the availability of essential commodities in its jurisdiction and assess demand of commodities depending upon the needs of the local area.	2. To assess coverage of consumers by Fair Price Shop, especially of the weaker sections.	2. To discharge duties as grievance redressal agency and issue directives to Fair Price Shops when required.
	3. To plan and taken steps for the elimination of bogus ration cards.	3. Preparation and issue of ration cards.
	4. To plan/review and recommend the opening of fair price shops in its jurisdiction.	4. Elimination of bogus ration cards.
	5. To coordinate schemes of Public Distribution System with other welfare schemes.	5. To decide the location of Fair Price Shops.
	6. To send reports and returns about Public Distribution System to Zila Parishad.	6. To arrange for the running of a Fair Price Shop where required by mobilising local resources/ finance.
	7. To disseminate information about consumer protection/welfare.	7. Assist Panchayat Samiti in preparing plan of action to link Public Distribution System with J. R. Y, I. R. D. P., I.C.D. S., D.W.C.R.A., mid day meals scheme etc.

A. Other Afforestation Scheme :

1. Finalization of micro plans proposed by Panchayat Samitis in consultation with D.F.O. concerned and approval thereof.	1. Formulation of Plans in respect of lands identified by the Gram Panchayats in co-ordination with concerned Range Officers. This will also include organising nursery raising.	1. To identify village common lands, other community and non forest lands for development of village wood lots in consultation with the local forest guards/Block officers. This will also include location of site, species to be planted and details of such areas which need maintenance.
2. Submission of Annual Plan of operation to Forest Department and allotment of funds from Forest Department to Zila Parishads for further allocation of budget to Panchayat Samitis/Gram Panchayats. Fixing of targets thereof as per approved micro plans.	2. To ensure the execution of micro plans through Gram Panchayats as per the physical/financial targets fixed.	2. Execution of micro plans by Gram Panchayat.
3. To submit accounts and physical and financal report to Forest Department.	3. Submission of consolidated accounts and reports to Zila Parishad.	3. Submission of monthly accounts and physical and financial reports to Panchayat Samities.
4. Monitoring/evaluation of activities.	4. Ensuring management/protection responsibilities of Gram Panchayats.	4. Taking over of management/responsibilities of assets created, which include maintenance and protection of these assets.
5. Resolving disputes, if any, regarding benefit sharing and monitoring thereof.	5. To act as a facilitator and ensure benefit sharing.	5. Benefit sharing out of the assets so created as per the policy of the Government.
Mointoring of the execution of the action plans.	6. Approval of the action plan.	6. Proposal on the nature of investment of the benefits so accrued as above for developmental activities and execution thereof.

1	2	3
B. Forest Fires :		
7. Co - ordination/supervision and monitoring thereof.	7. To issue direction to Gram Panchayats regarding different measures to be adopted for its prevention.	7. To enlist the co-operation of the local people to protect forest from fires and to help Forest Department in extinguishing forest fires by constituting Fire Protection Committee.
8. To recommend to Forest Department action against major defaulters such as suspension of T. D. rights as per the Forest Settlement	8. To recommend action against major and habitual defaulters and to report concerned authorities of the Department.	8. To report the defaulters who do not co-operate in extinguishing fires.
9. To monitor the forest fire cases and recommend awards for the Panchayats and individuals doing exemplary work. The award amount will be paid through Forest Department.	9. To send consolidated reports.	9. To submit periodical reports.
C. Minor Forest Produce :		
10. To popularise the concept of MFP plantations and returns thereof.	10. To monitor the cases of over exploitation and submit recommendations to Forest Department for its regulation.	10. To assess the availability of minor forest produce and report any incidence of its misuse.
D. Encroachment Cases. :		
11. To liaison with the Forest Department for ejectment.	11. To send the consolidated monthly report to Range Officer for action.	11. To pervent andreport the encrochment cases to DFO concerned.
E. Illicit Felling/Poaching :		
12. To educate masses against illicit felling and poaching, monitoring of offences of illicit felling/poaching.	12. To send the consolidated report to range officer for action.	12. To prevent and report the cases of illicit felling/poaching to the DFO concerned and take cognizance of patrolling of Forest Guards in their jurisdiction.

	14. Supervision of soil conservation work of the Forest Department.	14. Supervision of soil conservation work of the Forest Department.
	15. To supervise the protection of wild life.	15. To supervise the protection of wild life.
	HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT	
1. Formation of Health & Family Welfare Advisory Committee to oversee the functioning of C.H.C.'s and Rural Hospitals, improvement thereof and ensure that all the functionaries of these institutions are residing at the places of posting. However, the functioning of Zonal Hospitals, District Hospitals and Referral Hospitals are excluded from the purview of the Committee. The Committee shall be chaired by Chairman of the Zila Parishad and its members shall be Medical Superintendents of these hospitals, B.M.Os. and Zila Parishad members.	1. Construction and maintenance of Health Sub-Centres and staff quarters.	1. Formation of Health & Family Welfare Advisory Committee for sub-centres consisting of Panchayat members, opinion leaders, trained birth attendant Male/ Female Health Workers, NGO representatives etc. to oversee the functioning of each health institutions improvement thereof and ensure that the functionaries of the sub-centre are residing at the places of posting. The Committee shall be chaired by the Pradhan of the Gram Panchayat in whose area institution falls.
2. The Committee shall devise strategy to boost IEC campaign in respect of control measures for all communicable diseases like T. B., Leprosy, AIDS etc. as well as all other National Programmes.	2. Construction and maintenance of Community latrines in the Samiti areas with the help of local panchayat.	2. Sanitation, cleaning of roads, drains, chlorination of wells/ bowlies and destruction of stray dogs and their disposal.

1	2	3
3. Planning of Family Welfare, immunization and health education camps for the community.	3. Organise health and family welfare camps and exhibitions in Melas in order to promote awareness of National Health Programmes.	3. Organising School health check up programmes.
	4. Take all effective measures with the help of health functionaries to control epidemics in their areas.	4. Helping the D. D. T. spray team during the season.
	5. Formation of Health & Family Welfare Advisory Committees for all health institutions upto the level of C. D. and P. H. C. comprising of B. M. O., Samiti members, N. G. O. representatives, Male/Female supervisors etc. to oversee the functioning of the Health institutions, improvement thereof and ensure that all the functionaries of C. D. and P. H. C. are residing at the places of posting. The Committee shall be chaired by Chairman of the Panchayat Samiti.	5. Motivating the community for adopting family planning methods/immunization etc. and organising the camps.
		6. Reporting the outbreak of Gastroenteritis and any other epidemic and starting containment measures with the help of Health Committees.
		7. Registration of births and deaths.
		8. Construction and maintenance of village drains and disposal of wastes.

HORTICULTURE DEPARTMENT

1. Review and monitoring of all the functions and activities in respect of Horticulture entrusted to Panchayat Samitis.
2. Maintaining co-ordination and liaison with the department of Horticlture in respect of all the Horticulture Development Programmes.
3. Organising campaigns, fairs, meets, exhibitions, seminars etc.
4. Co-ordination and monitoring of procurement and distribution of packing material for horticulture produce.
5. Co-ordination and monitoring of procurement of fruits under Market Intervention Schemes/ support price.

1. Review, monitoring and supervision of all functions and activities in respect of horticulture entrusted to Gram Panchayat.
2. Organising horticultural inputs distribution system (other than fungicides/pesticides.
3. Organising farmers training camps, study tours, seminars etc.
4. Organising of demonstrations on improved varieties / technology/ package of practices etc. for increasing horticultural production.
5. Conducting Village-wise horticultural census.
6. Preparation of action plan for each water-shed.
7. Supervise the procurement and distribution of plants by the Block Agency.

1. Identification and selection of beneficaries for different horticultural subsidy schemes for small & marginal farmers.
2. Promotion of farmers clubs and horticultural producers co-operative societies.
3. Supervising collection centres for fruits under Market Intervention scheme (MIS)/Support price scheme.

INDUSTRIES DEPARTMENT

1. The District Action Plan of the Department as per the discussion with Panchayat Samiti will be presented to Zila Parishad by the General Manager, District Industries Centre, for approval before he submits to Director of Industries.

1. The draft of District Action Plan of the Department as prepared by the General Manager, District Industries Centre, will be discussed with the Panchayat Samiti in which the Lead Bank Officer will be associated.

1	2	3
2. The General Manager, District Industries Centre, will send a list of cases which have been recommended to various Banks every month. He will also furnish information with regard to the status of past cases which had already been recommended. The respective Banks will send a list of defaulters to Zila Parishad every month for monitoring. The General Manager, D. I. C., will provide similar information with regard to departmental loans.	2. The General Manager, District Industries Centre will endorse a copy of the letter to the concerned Panchayat Samiti *vide* which a recommendation is made to any Bank for grant of industrial loan to the Industrial units.	2. The General Manager, District Industries Centre, will endorse a copy of letter to the concerned Gram Panchayat *vide* which a recommendation is made to any Bank for grant of industrial units.
3. The Zila Parishad will collect the information with regard to skills available, the list of interested persons who are interested to acquire the skills as per the requirements of the industrial units, prioritise the same and send to the Department of Industries for organising the skill development training programmes.	3. The Department of Industries will bring to the notice of the concerned Panchayat Samiti the manpower/skill requirements of the proposed industry to be set up in the areas. The Panchyat Samiti will provide information with regard to availability of skills in that area. In case the particular type of skill is not available, the Panchayat Samiti will bring to the notice of the Zila Parishad the list of the persons interested to acquire the requisite skill.	
4. Zila Parishad will collect the information with regard to the conducting of Industrial Awareness/Entrepreneurship Development Programme and target. group *viz* SC/ST, Women, Exservicemen, general categories etc. for which the programmes are proposed. Zila Parishad will then prioritise and send the same to the	4. Panchayat Samiti shall identify the locations in their respective area of operation where there is a potential of conducting Industrial/Awareness Programmes/Entrepreneurship Development Programmes. The target groups for which these programmes are proposed will be sent to the Zila Parishad.	

	Department of Industries alongwith their recommendations for conducting the programmes.		
5.	Training under Prime Minister Rozgar Yojna (PMRY) for the beneficiaries in whose favour loan is sanctioned for setting up of self employment ventures under Industry, Service & Business sectors is arranged by the General Manager, D. I. C. at the District, Sub-Division and Block level as per guidelines/instructions of Development Commissioner (S. S. I.). New Delhi. Member(s) nominated by Chairman, Zila Parishad/Panchayat Samiti can be included in the District Task Force Committee.	5. Identification and selection of artisans/beneficaries for Prime Minister Rozgar Yojna (PMRY), Rural Industries Plan (RIP)/Rural Artisans Plan (RAP) at Block level. Chairman Panchayat Samiti, may nominate one member for identification/selection of P.M.R.Y. and R.A.P./R.I.P. beneficiaries and Extension Officer (Industries) of the Block shall be made Member-Secretary of the Selection Committee. As regards credit facilities for Industry, Service & Business Sector under P. M. R. Y., the cases are prepared/processed by D. I. C. headed by the General Manager.	
6.	—	6. (1) The Panchayat Samiti will consider the recommendation in respect of Sericulture activities of the Gram Panchayat and will take final decision keeping in view the budget position. (2) At the same time it can *suo-motu* initiate proposals for setting up of sub-centres in any panchayat under its jurisdiction. (3) It will look after the marketing of cocoons. (4) The concerned Divisional Sericulture Officer will implement the decisions of the Panchayat Samitis subject to the availability of funds under the schemes.	6. Gram Panchayat will identify suitable place of land for establishing mulberry farm/nurseries and chowki centres and recommend to the Panchayat Samiti for taking appropriate decision.

1	2	3
. (1) Zila Parishad will consider the proposals forwarded by Panchayat Samitis and take a decision as it may deem fit.	(1) Panchayat Samiti will examine the proposals submitted by the Gram Panchayats of their areas and take appropriate action before forwarding the recommendations to the Zila Parishad.	7. Gram Panchayat can forward proposal for setting up Industrial Areas/Estates in case sufficient chunk of land is available in the Panchayat.
(2) Zila Parishad can also *suo motu* identify land for such purposes after taking views, if it considers necessary, of the respective Panchayats/Panchayat Samitis.	(2) The Panchayat Samiti concerned may also, of its own, identify land for establishing Industrial Areas/ Estates within their jurisdiction and submit the proposal to Zila Parishad for decision.	
(3) After the Zila Parishad has considered, identified the land and approved the proposal, the same will be submitted with its recommendations through the General Manager, D. I. C., to the Director of Industries for further action.		
8. At present prospective entrepreneurs after registration and approval of their project, apply for the allotment of plot/shed in the Industrial Area to the General Manager, District Industries Centre. The Plot Allotment Committee at the District level under the charmanship of General Manager, D.I.C., after consideration of all the applications for allotment of plots/shed make the allotment to the entrepreneurs, depending upon the project and availability of plots/sheds, keeping in view the allotment policy in view. One member of the Zila Parishad will be nominated on the Plot Allotment Committee.		

1. Identification of potential schemes including water harvesting covering more than one block.	1. Prevention and control of water pollution.	1. Routine maintenance of hand pumps staff to be provided by the Department.
2. To bring to the notice of appropriate authority of the I. P. H. Department the cases of gross misutilization of funds, corrupt practices etc. by the staff of the the Department, Contractors and Sub-Contractors while executing various schemes.	2. Identification of potential schemes including water harvesting covering more than one panchayat.	2. Routine maintenance of drinking water and irrigation schemes which have been executed at a cost of one lakh and below.
	3. To bring to the notice of appropriate authority of the I. P. H. Department the cases of gross misutilization of funds, corrupt practices etc. by the staff of the Department, Contractors and Sub-Contractors while executing various schemes.	3. Prevention and control of water pollution.
		4. Identification of poteniial schemes within Gram Panchayat area.
		5. Information regarding functioning and condition of water supply schemes will be given by the Panchayat to the prescribed authority.
		6. To bring to the notice of appropriate authority of the I. P. H. Department the cases of gross misutilization of funds, corrupt practices etc. by the staff of the Department, Contractors and Sub-Contractors while executing various schemes.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

1. Identification of village link roads, mule roads, village paths,	1. Identification, construction and maintenance of mule roads and	1. Identification of village link roads.

1	2	3
culverts and foot bridges upto 10 mtrs. span on these roads and paths.	identification of village link roads,	
2. Supervision of execution of works by Panchayat Samitis like construction of mule roads, culverts and foot bridges upto 10 mts. span on these paths and roads.	2. Construction and maintenance of buildings belonging to Panchayat Samitis.	2. Identification, construction and maintenance of village paths, culverts and lanes.
3. Construction and maintenance of buildings belonging to Zila Parishad.	3. Maintenance of those rural roads which may be transferred by P. W. D. to Panchayati Raj Institutions.	3. Construction and maintenance of small foot bridges upto 10 metres span on Nallahs/streams falling on village paths.
4. Supervision of construction of buildings belonging to Panchayat Samitis and Gram Panchayats. Constructions/maintenance of Jhullas across rivers/streams on village paths/mule paths covering more than two blocks.	4. Construction and maintenance of Jhullas across rivers/streams on village path/mule paths within its area.	4. Construction and maintenance of buildings belonging to the Gram Panchayats.
5. To bring to the notice of appropriate authority of the Public Works Department the cases of gross misultilisation of funds, corrupt practices etc., by the staff of the Department contractors and sub-contractors while executing various schemes.	5. Supervision of construction of buildings by Gram Panchayats.	5. To bring to the notice of appropriate authority of the Public Works Department, the cases of gross misutilization of funds, corrupt practices etc. by the staff of Department contractors and sub-contractors while executing various schemes.
6. Maintenance and running of boats and ferries.	6. Supervision of construction of village paths, culverts and village lanes. 7. Supervision of construction of small foot bridges upto 10 mtrs. span falling on village paths/	

	8. To bring to the notice of appropriate authority of the Public Works Department the cases of gross misutilization of funds, corrupt practices etc., by the staff of department contractors and sub-contractors while executing various schemes.	
	REVENUE DEPARTMENT	
1. To supervise the duties and functions at block level, regarding revenue matters.	1. To supervise the work entrusted in revenue matters to Panchayats and formulate policy at block level for removal of encroachments on Government land at block level.	1. Prevention of encroachments on village common land the management of which is entrueted to the Panchayat.
2. To assist the revenue officials in identification of landless/housless persons and formulation of policies for utilization of Government land giving no objection certificate for giving such land on lease at District level.	2. To assist the revenue officials in identification of landless/houseless persons for utilization of Government land and giving no objection certificate for giving such land on lease at block level.	2. Patwaris will paste his monthly working chart on the notice board of patwarkhana indicating the working days he will visit the Panchayat areas. Any departure will be reported to the Gram Panchayat concerned.
		3. To ensure that all eligible kisans are issued Kisan Pass Books and the same are updated regularly.
		4. If any Kisan faces difficulty in getting a copy of any revenue record he can apply to the Panchayat who will direct the concerned Patwari to issue the requisite copy of the revenue record through Panchayat within seven days.
		5. The Patwari Mohal shall place a copy of the records of rights like

1	2	3
		Jamabandi and Wazib-ul-urz at the panchayat Headquaters for the perusal of the general public. 6. Helping administration in providing relief in natural calamities. 7. Removal of encroachment on public property and land. 8. To ensure protection of boundary pillars and impose suitable punishment in case of destruction or defacement. 9. Maintenance of essential statisties relating to the Panchayat. **Implementation of Land Ceiling Measures:**
3. Co-ordination with the legally constituted machinery in all stages of its work and rendering of necessary assistance to it either directly or through the PS and/or GP, as the case may be.	3. Assistance to the legal machinery in conduct of legal proceedings (e.g. publication of notice in the entire area, identification of land in different GP areas etc.).	1. Assist in identification of potential surplus land owner/their total land in the Gram Panchayat area. 2. Assistance to the legal machinery in conduct of legal proceedings. 3. Assistance in identification of families/individuals needing allotment of land.
4. Creation of publih opinion for facilitating the work of land ceiling as well as other elements of land reforms.	4. Co-ordination of the work as between the GPs.	4. Assistance in organising land raising measure for individual allottees or groups of them. **Implementation of Tenancy measures :** 1. Assistance in identification of tenancy (including share tenancy)

		2. Assistance to the legal machinery in its task of securing as well as regularising tenancy rights, or conferring ownership rights, as the case may be.
		3. Towards this end creation of public opinion, marshalling of documentary and non-documentary evidences, paritcularly on issue of possession and use of the lands concerned.
		Land Consolidation :
5. Periodic monitoring of the work in the entire ZP areas and advising/ instructing PSs and GPs on matter relating to implementation and monitoring.	5. Compilation of GP-wise data on land reforms measures and monitoring progress of such measures for the PS area. Assisting the ZP in monitoring for ZP area.	1. Securing active and continuing involvement of inhabitants of local area in different stages of the operation as set out in the law *e.g* accordance approval to the draft plan.
	6. Report regarding wrong change in revenue entries, malpractices, tempering of records and issue of wrong certificate and not issuing certificate in genuine case to be reported to SDO(C) of the area.	2. Towards this end assistance to the machinery in compilation of un-documented date on issues like possession and use of land, different gradation of land rights, status of common land and other common property etc.
		3. Assistance to the legal machinery in ensuring that after consolidation, possession of assigned plots/holdings actually accord with the implemented scheme of consolidation.

1	2	3
		4. Gram Sabha is authorise to pass resolution to undertake the consolidation operation.
		Participation in updating and Maintenance of land Records.
		1. Assisting in continuous updating of data relating to use season-wise of agricultural land or assistance in doing so to the designated machinery where it has been separately constituted.
		2. Assist in periodic updating of data relating to the actual status of village commons that is pusture wasteland, water reservoirs waterways, roads, embankments etc.
		3. Assistance to the legal machinery in the updating of land records (record of rights) and mutation proceedings.
		Protection and Maintenance of Village Common :
		1. Primary responsibility for keeping common property of local nature in good condition. Keeping watch over them so that they are not encroached upon or converted to uses not in the interest of community.
		2. Identify encroachment as well as conversion of illegal or wrong

		3. Provision of assistance in and collection of evidence towards the conduct of the proceedings by such authority.
		4. Creation of public opinion in favour of use of soil only in consonance with its properties, gradients etc.

RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

1. Evaluation of all poverty alleviation programmes and the coverage of women, SC, ST & other IRDP beneficiaries in these programmes.	1. To ensure that the funds provided by the DRDA to the Gram Panchayats are utilised as per the prescribed guide-lines within its jurisdiction.	1. Identification and selection of beneficiaries for IRDP/TRYSEM/DWCRA.
2. Developing marketing infrastructure/marketing network/tie up arrangements for the products in Rural Areas.	2. Organising training/awareness camps for IRDP beneficiaries.	2. Supervise the implementation of IRDP/DWCRA/TRYSEM schemes.
3. Ensuring the focus of development programmes on environment and natural resources development.	3. Co-ordinating with Banks and other Financial Instituti ons for release of subsidy and loans.	3. Ownership and maintenance of the community assets viz. Pnachayat Ghars, Community Centres, Mahila/Yuvak Mandal Bhawans and IRDP stalls etc.
4. Monitoring loan and subsidy disbursement in co-ordination with Banks and other Financial Institutions in Rural Development Programmes.	4. Monitoring the distribution of Vikas Patrikas and Credit Books to the beneficiaries.	4. Assisting Banks and other financial Institutions in the recovery of loans.
5. Wide publicity of watershed guidelines amongst people of the concerned areas.	5. Monitoring the use of assets and schemes under IRDP etc.	5. Helping IRDP beneficiaries to procure raw material and marketing of products.

1	2	3
6. Identification of local viable technologies.	6. To help Banks and other Financial Institutions for recovery of loans.	6. Preparing village plan for works under JRY/IDRY/EAS and their implementation.
	7. To oversee the implementation of various insurance schemes for rural poor.	7. Obtaining technical assistance from technical personnels of the concerned department.
	8. To monitor and co-ordinate supply of foodgrains to the Gram Panchayats under JRY/EAS.	8. Identification of beneficiaries under employment generation programmes.
	9. To supervise the implementation of IAY, GKY, RSP and CRSP there will be an Implementation Committee under the Chairmanship of Chairman Panchayat Samiti, S.D.O. (C), BDO concerned and some Panchayat Samiti members would be members of this Committee. The Committee will also look into the complaints regarding wrong selection of beneficiaries under these schemes.	9. Distribution of foodgrains under JRY/IJRY/EAS.
	10. Prevention of misuse of community assets of the Panchayat Samiti.	10. Maintenance of assets created under JRY/IJRY/EAS.
	11. Organise auction of produce from community assets of Panchayat Samiti.	11. Selection of beneficiaries under IAY & GKY.
	12. Supervision and monitoring of Central/State Rural Sanitation Programmes executed by the Gram Panchayats.	12. Implementation of Central & State Rural Sanitation Programme.
	13. Development and maintenance of places for Fairs/Mandis/weekly markets at Panchayat Samiti level.	13. Reporting against misuse of assets/subsidy and loans to the concerned department.
		14. Motivation and formation of village level user groups for the watershed programmes.

		15. Help the PIAs and other agencies in the implementation of the Watershed Development programe.
		16. Development and maintenance of places for village fairs/ markets.
		17. Organise auction of produce from community assets of Gram Panchayat.
		18. Helping in identification and selection of NSAP beneficiaries in consultation with the Health & Social & Women Welfare Departments.
		19. Implementation of National Programme of improved Chullahs.
		20. Maintenance of cremation grounds and grave yards.

SOCIAL AND WOMEN'S WELFARE DEPARTMENT

A. Integrated Child Development Services :		
1. Monitoring the function of the scheme in the district.	1. To guide and assist the project staff working in the Panchayat Samiti area.	1. Assist in collection of beneficiaries centres and management of Anganwadi Centres except Nutrition. Transfer of staff (Anganwadi worker/ Helpers).
	2. Construction of Anganwadi Centres in the Gram Panchayats. Funds to be transferred.	
	3. Provide infrastructural facilities and other logistic support to facilitate implementation of the programme.	
B. Welfare of disabled :		
2. Inspection, Supervision and Monitoring of the Voluntary	4. Identification of disabled persons/leprosy patients and co-ordination with	2. Identification of disabled persons/ eprosy patients and co-ordination

1	2	3
Organisations in the District receiving grant-in-aid from the Ministryof Welfare, Govt. of India, for rehabilitation of the persons with disabilities.	the Zila Parishads for their rehabilitation.	with the Block and Zila Parishad for their rehabilitation.
3. Indentification and promotion of Voluntary Organisations for assisting the disabled persons/ leprosy patients, with grant-in-aid from the Ministry of Welfare.		
4. Organise Support Meet and cultural programme for people with disabilities.		
C. Welfare of aged :		
5. Identifying the destitute aged persons and helping them in taking shelter with the voluntary organisation which receives grant-in-aid from the Ministry of Welfare/State Government for running and maintaining old age homes.	5. Co-ordination with the Zila Parishad.	3. Co-ordination with the Panchayat Samiti.
D. Drug abuse prevention :		
6. Building awareness and educating people about ill effects of the drug abuse.	6. Co-ordination with the Zila Parishad.	4. Co-ordination with the Panchayat Samiti.
7. Identify and promote voluntary organisations to deal with the drug addicts through a well rounded up programme of motivation counselling treatment and		

8. Inspection of homes for the juvenile delinquents	7. Co-ordination with the Zila Parishad for above functions.	5. Co-ordination with the Panchayat Samiti for above functions.
F. Eradication of untouchability :		
9. Co-ordination with the District officials in implementation of provisions of PCR Act, 1955.	8. Survey of untouchability prone areas, selection of gram Panchayats doing best work in the area of removal of untouchability for giving awards, organising camps to create awareness about the provision of the PCR Act, 1955. Transfer of funds.	6. Identification of discriminatory practices against Scheduled Castes with special reference to :— (*a*) accessibility to common drinking burial places. (*b*) accessibility to common drinking water source. (*c*) use of separate utensils in village tea stalls. (*d*) refusal to offer services by barber and washerman. (*e*) taking marriage processions (barat). The concerned Gram Panchayat should ensure that no such discriminatory practices exist in the village, and if they are found, adequate steps be taken under the provisions of the PCR Act, 1955 for preventing it.
10. Celebration of 'Removal of Untouchability week' on 2nd October every year. Transfer of funds.		
G. Curbing Atrocity against Shch. Castes/Sch. Tribes :		
11. Co-ordination in the implementation of Sch. Castes/Sch. Tribes (Prevention of Atrocity) Act, 1989.	9. Organising camps for creating awareness among people about the provisions of the Act. Transfer of funds.	7. Disbursing monetary relief to the victims of the atrocity at the prescribed rates. Funds as and when demanded.
***H.* Liberation and Rehabilitation of Scavengers :**		
12. Identification and varification of the applicants under liberation of scavengers.		

7. Improvement of Harijan Basties;	10. To prepare estimate for pavements, streets, drains, electric point etc. and forward it to Zila Parishad.	8. To forward proposals to the Panchayat Samiti for preparing estimates. An execution of works under the scheme upto Rs. 25,000/-. Transfer of funds.
	11. Scrutiny/sanctions of proposals received from the Gram Panchayat upto Rs. 25,000/-.	
	12. Scrutiny/sanction of proposals received from Gram Panchayats upto Rs. 25,000/- for construction/repair of pavement, drains water at resources etc. Sanction upto Rs. 25,000/-. Transfer of funds.	
K. Non-Governmental Organisations :		
13. Monitoring, supervision and inspection of Non-Governmental Organisations receiving grant-in-aid from the Ministry of Welfare/Human Resource Development & State Government for the welfare programmes.		
14. Inspection of Institutions aided by the State Govt. Indian Council for Child Welfare and State Social Welfare Advisory Board such as Creches and Anganwadis.		